प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

09 अगस्त, 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन वित्त एवं संचार आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या 16 की वर्ष 2023 में संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) और वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) की अनुपालना लेखापरीक्षा से प्राप्त हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2021-22 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में सामने आये, लेकिन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके।

डाक विभाग के विरासत भवनों का संरक्षण

संरक्षण नीति और एक समर्पित संगठनात्मक संरचना के अभाव के कारण संरक्षण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। डाक विभाग द्वारा अपने विरासत भवनों की पहचान और प्रलेखन पूरा करने में देरी के कारण समय के साथ उनकी स्थिति और खराब हुई। विभाग ने अपने विरासत भवनों के संरक्षण के लिए कभी भी विशेष एजेंसियों को शामिल नहीं किया और सिविल कार्यों को पूरा करने के दौरान मौजूदा नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया। विभाग को इसकी अनिवार्य गतिविधियों के लिए आवंटित धन अपर्याप्त था। अपर्याप्त योजना और खराब प्रबंधन के साथ-साथ समय-समय पर भौतिक सत्यापन न होने से विरासत भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को और बढ़ा दिया। इस प्रकार, विभाग के पास अपने विरासत भवनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक उद्देश्य और एक उपयुक्त रणनीति का अभाव था।

हमने डाक विभाग से पर्याप्त संसाधनों के आवंटन सहित सर्किलों में विरासत संरचनाओं की पहचान और संरक्षण / रखरखाव में अपेक्षित स्पष्टता लाने के लिए एक व्यापक संरक्षण नीति विकसित करने की सिफारिश की है। हमने यह भी सिफारिश की, कि शीघ्र निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए विरासत शाखा (सितंबर 2020 में बनाई गई) की शक्तियों और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की

आवश्यकता है। डी ओ पी में सभी विरासत भवनों से संबंधित मामलों को पर्याप्त रूप से संभालने के लिए इसे नोडल विभाग / समर्पित सेल बनाया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.1)

अजमेर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना पर व्यर्थ व्यय

मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) बड़े क्षेत्र के सौर फोटो वोल्टाइक पैनल और दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने से पहले अजमेर और उसके आस-पास औद्योगिक विकास का सर्वेक्षण करने में विफल रहा। खराब / अकुशल योजना के साथ-साथ अप्रभावी निगरानी के कारण अजमेर में इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर (ई टी डी सी) की स्थापना पर ₹21.83 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

"स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद चित्रण (आई एम आर आई)" परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब

प्रस्तावित चुंबक के डिजाइन की वैधता के लिए सलाहकार की नियुक्ति में देरी के कारण चुंबक के निर्माण से सम्बन्धित प्रगति में काफी देरी हुई। नतीजतन, कम लागत वाले एम आर आई स्कैन प्रदान करने का परियोजना उद्देश्य अभी तक परियोजना आयोजन और निष्पादन में कमियों के कारण प्राप्त नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

भारत संचार निगम लिमिटेड में संपदा प्रबंधन

बी एस एन एल के पास पर्याप्त भूमि और अचल परिसंपत्ति है, लेकिन उसने व्यापक संपदा प्रबंधन नीति स्थापित नहीं की है। यहां तक कि एक भूमि प्रबंधन नीति, जैसा कि पी ए सी को आश्वासन दिया गया है, व्यापक रूप से तैयार नहीं की गई है। कंपनी के पास आज तक अपनी अचल परिसंपत्तियों का समायोजित और वैध केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं है।

पी ए सी को आश्वासन के बावजूद, बी एस एन एल के पास अपनी अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व के अधूरे रिकॉर्ड हैं, जो बिक्री या किराये के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग में बाधक है। ऐसे मामलों में भी जहां कंपनी के पास स्वामित्व का स्पष्ट अधिकार है, वह अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपनी खाली भूमि और निर्मित स्थानों का व्यावसायिक उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि इस मुद्दे को पी ए सी द्वारा उठाया गया था, कंपनी अभी भी अतिक्रमण के खतरे से जूझ रही है और अपनी

संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। मुद्रीकरण के लिए संपत्तियों के चयन और प्रस्ताव में उचित प्रयास की कमी के कारण लक्षित मुद्रीकरण गंभीर रूप से बाधित हुआ।

हमने सुझाव दिया कि बी एस एन एल विभिन्न डेटा सेटों का मिलान कर सकता है और अचल परिसंपत्तियों के सटीक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है। बी एस एन एल उन एजेंसियों के साथ कानूनी अधिकारों और समझौतों को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य बिंदुओं के साथ एक समयबद्ध योजना भी बना सकता है, जिन्होंने कंपनी की भूमि को पट्टे पर लिया है या कब्जा किया हुआ है।

(पैराग्राफ 4.1)

बी एस एन एल ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना

दूरसंचार आयोग ने, भुगतान के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बी एस एन एल के टेलीफोन एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने वाले 25,000 हॉटस्पॉट वाई-फाई स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को दिसंबर 2016 में मंजूरी दी। इस परियोजना को वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) से वित्तपोषित किया जाना था।

बी एस एन एल ने ग्रामीण एक्सचेंजों में वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करने और दूरसंचार आयोग को प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यक उचित सावधानी नहीं बरती। परिणामस्वरूप, 13.77 प्रतिशत साइटों को बंद कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया और इन एक्सचेंजों में हॉटस्पॉट स्थापित करने पर किया गया व्यय निष्फल था। इसके अलावा, दस टेलीकॉम सर्किलों में 700 वाई-फाई हॉटस्पॉट को चालू करने में 790 दिनों (26 महीने तक) तक की देरी हुई थी। इसके अलावा, स्थापित किए गए वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ने के साथ डाउनटाइम पेनल्टी भी बढ़ गई। इसके कारण, बी एस एन एल ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान संशोधित परियोजना लागत का 9.45 प्रतिशत तक भारी जुर्माना अदा किया।

हमने सिफारिश की, कि बी एस एन एल को किसी भी योजना के कार्यान्वयन के मुद्दों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय लोक निधि का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; बी एस एन एल को जरूरत पड़ने पर निर्धारित वाई-फाई हॉटस्पॉट को नवीनतम तकनीक में अपग्रेड करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्थिर राजस्व अर्जन मॉडल तैयार करना चाहिए और स्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट्स के प्रभावी प्रदर्शन और रखरखाव की ओर भी ध्यान देना चाहिए, उचित प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए और इस तरह डाउनटाइम पेनल्टी को कम करना चाहिए।

(पैराग्राफ 4.2)

बी एस एन एल में आधार नामांकन केंद्रों में आधार नामांकन किट की अनुपयोगिता

बी एस एन एल ने 2018-19 के दौरान ₹77.88 करोड़ मूल्य के 6,000 आधार नामांकन किट खरीदे। उनमें से 3,941 किट दिसंबर 2022 तक अनुपयोगी रहीं। इसके परिणामस्वरूप ₹51.15 करोड़ की सरकारी निधि अवरुद्ध हो गई। इसके अलावा, यू आई डी ए आई ने बी एस एन एल पर ₹0.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

(पैराग्राफ 4.3)

संशोधित टैरिफ दरें लागू नहीं करने से राजस्व की हानि

हमने देखा कि कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट, आई डी आर लिंक के लिए निर्धारित शुल्क लागू करने के बजाय ओ एफ सी / कॉपर मीडिया के लिए लागू सामान्य पट्टा लाइन दरों पर इंटरमीडिएट डेटा रेट (आई डी आर) सैटेलाइट लिंक के लिए बिल जारी करता रहा। इसी तरह, ओड़िशा टेलीकॉम परिमण्डल ने समय-समय पर बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा संशोधन के बाद वार्षिक किराये के बिलों को संशोधित नहीं किया। कम बिलिंग की कुल राशि ₹4.26 करोड़ (₹0.77 करोड़ के कर को छोड़कर) थी।

(पैराग्राफ 4.4)

सुरक्षा धागा (चुंबकीय) की खरीद पर व्यर्थ व्यय

एस पी एम होशंगाबाद ने ₹7.82 करोड़ मूल्य का 7.5 मीट्रिक टन अतिरिक्त सुरक्षा धागा (चुंबकीय) खरीदा, जो पांच साल से अधिक समय से स्टोर में बेकार पड़ा हुआ था और बाद में स्टॉक रजिस्टर में ₹1 के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर अनुपयोगी वस्तु घोषित किया गया, जो दर्शाता है कि कच्चा माल अब उपयोग में नहीं लाया जा सकता था।

(पैराग्राफ 5.1)